

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक  
(गुरारी लाल शर्मा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

29 / 2020  
02.11.2020

तेजकरण पुत्र केसरा जाति बैरवा निवारी केरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक  
03.09.2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थिति : (1) श्री शिवराज टाण्डी, अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 12.03.2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 99/5 रकबा 10 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम केरिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कागून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मान की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अपीलांट को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया और नहीं मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट को पूर्व में उक्त भूमि से बेदखल किये जाने के संबंध में कोई सक्षम साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता हो। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलांट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अपीलांट ने उक्त भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ



938



अधीनस्थ जिला कलेक्टर  
टोंक

पत्र अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामील हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इरारो पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 99/5 रकबा 10 बिरवा किरम चरागाह वाके ग्राम केरिया तहसील मालपुरा पर कब्जा बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जे के संबंध में तहसीलदार मालपुरा से जांच करवाने पर तहसीलदार मालपुरा ने उनके पत्र क्रमांक 3324 दिनांक 31.12.2020 से अवगत कराया है कि आरजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम केरिया पर अब वर्तमान में अतिक्रमी द्वारा मौके पर से भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है और वर्तमान में उक्त चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2020 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलाण्ट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलाण्ट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



12-3-21  
(महाराज लाल शर्मा)  
बाबरीयत पत्रावली  
अति.जिला क्लर्क, टोक